



International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

ग्राम पंचायत निर्वाचन में मतदान व्यवहार: मुरैना जिले के पंचायत आम निर्वाचन 2015 एवं 2022 के विशेष संदर्भ में एट अध्ययन

पुष्पेन्द्र धाकड़

शोध छात्र, विषय. राजनीति शास्त्र
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)
डॉ. जयश्री त्रिवेदी
प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष,
राजनीति शास्त्र,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

Paper Received date

05/05/2025

Paper date Publishing Date

10/05/2025

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15567989>



ABSTRACT

यह शोधपत्र मुरैना जिले के 2015 और 2022 के ग्राम पंचायत आम निर्वाचन में मतदाताओं के व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत के लोकतंत्र में ग्राम पंचायत चुनावों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर जनभागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। मुरैना जिले की जातीय, सामाजिक और राजनीतिक संरचना ने इन चुनावों को प्रभावित किया है। अध्ययन में पाया गया कि जाति, वर्ग, लिंग और धर्म मतदान व्यवहार को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, परंतु निर्णय अब भी पारिवारिक और सामाजिक प्रभावों से जुड़ा है। प्रचार में माइकिंग, सोशल मीडिया और घर-घर संपर्क प्रभावशाली माध्यम रहे। मतदान केंद्रों की पहुंच, जागरूकता अभियान और आरक्षण नीति ने वंचित वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा दिया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक और तुलनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली और द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्रित की गई है। शोध से यह निष्कर्ष निकला कि मुरैना में मतदान व्यवहार केवल राजनीतिक दलों पर नहीं, बल्कि प्रत्याशी की सामाजिक छवि, विकास मुद्दों और जातीय समीकरणों पर भी निर्भर करता है। यह शोध लोकतंत्र की जमीनी मजबूती, महिला-युवा सशक्तिकरण और समावेशी शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्यबिन्दु: मतदान व्यवहार, ग्राम पंचायत चुनाव, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक जागरूकता, विकास आधारित मतदान

ग्राम पंचायत चुनाव का महत्व और मुरैना जिले की पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायत चुनाव भारत के लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं। ये चुनाव ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनकर विकास कार्यों और प्रशासन में योगदान दे सकते हैं। इन चुनावों के माध्यम से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है, बल्कि यह महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों को आरक्षण प्रणाली के तहत सशक्त करने का भी एक माध्यम बनता है। ग्राम पंचायतें गाँवों में जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

मुरैना जिला, जो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है, ग्राम पंचायत चुनावों की दृष्टि से एक राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण नागरिक पंचायत चुनावों में विशेष रूप से उत्साह से भाग लेते हैं और मतदान प्रतिशत भी अपेक्षाकृत अच्छा रहता है। मुरैना की पंचायत राजनीति में जातीय समीकरण, धनबल और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका अहम मानी जाती है। इसके बावजूद, हाल के वर्षों में इस जिले ने महिला सरपंचों और युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखा है, जो ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पंचायत चुनावों में युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाने में मदद की है।

ग्राम पंचायत चुनावों का लोकतांत्रिक महत्व

ग्राम पंचायतें भारत के त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम इकाई हैं। पंचायत चुनाव ग्रामीण जनता को शासन में सीधे भाग लेने का अवसर देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्कृति का विस्तार होता है। इससे नागरिक सहभागिता और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार ग्राम पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इससे लोकतंत्र में समावेशिता आती है और ये वर्ग निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं।

ग्राम पंचायतें जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि जैसे मुद्दों पर स्थानीय योजना और क्रियान्वयन करती हैं। जब ग्रामीण स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को दिशा दे सकते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में आम नागरिकों को भाग लेने का अधिकार है जिससे वे पंचों और सरपंच की कार्यप्रणाली पर निगरानी रख सकते हैं। यह जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जो किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। ग्राम पंचायत चुनावों से जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित होता है, जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व तैयार होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की निरंतरता का प्रतीक है।

मुरैना जिले की भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित मुरैना जिला, चंबल संभाग का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र है। इसकी सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में भिंड जिले से मिलती है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,989 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मुख्यतः समतल और उपजाऊ भूमि फैली हुई है। यह क्षेत्र चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित होता है, जो कृषि को जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाती हैं। यहाँ की जलवायु अर्द्ध-शुष्क है, जिसमें गर्मी अधिक तीव्र होती है और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700-900 मिमी के बीच होती है।

मुरैना की सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण है। यहाँ अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग (वर्ग), और सामान्य वर्ग के नागरिक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। जातीय समीकरण पंचायत चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की उच्चता, निम्न साक्षरता दर और आर्थिक असमानता सामाजिक ढाँचे को प्रभावित करते हैं। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और भूमि स्वामित्व असमानता ग्रामीण वर्ग विभाजन को गहरा करती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार देखा गया है, विशेष रूप से पंचायत चुनावों में आरक्षण के बाद। हालांकि, परंपरागत पितृसत्तात्मक ढाँचा आज भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पंचायत शासन के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है।

महिला, युवा, जाति और वर्ग आधारित मतदान व्यवहार

क्मीचंदकम (2009) ने महिला मतदाताओं के व्यवहार पर किए गए अध्ययन में यह पाया कि अनेक महिलाएँ अपने मताधिकार का प्रयोग पारिवारिक निर्देशों के अनुसार करती हैं, परंतु हालिया वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण अभियान, और स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव से यह प्रवृत्ति बदल रही है। युवाओं के मतदान व्यवहार पर शोध दर्शाते हैं कि वे अधिकतर मुद्दा आधारित मतदान करते हैं, विशेष रूप से रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास से जुड़े मुद्दों पर। Khatun (2019) द्वारा किए गए अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के मतदान निर्णय पर सामाजिक दबावों की पुष्टि हुई।

जाति आधारित मतदान व्यवहार पर हुए शोधों में यह पाया गया है कि उच्च और प्रभावशाली जातियाँ चुनावी रणनीति को नियंत्रित करती हैं, जबकि अन्य वर्ग अपनी जनसंख्या के बावजूद निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाते (Palshikar & Mishra] 2023)। वर्ग आधारित मतदाताओं, जैसे कृषक व मजदूर वर्ग, का मतदान अक्सर आर्थिक मुद्दों और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होता है।

मुरैना जिले में पूर्व आंकड़े व चुनावी रिपोर्ट्स

मुरैना जिले में पंचायत चुनावों पर सीमित लेकिन उल्लेखनीय क्षेत्रीय अध्ययन हुए हैं। मुरैना के मतदान रुझानों में जातीय समीकरणों की भूमिका सदा से महत्वपूर्ण रही है। स्थानीय चुनावी रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में मतदान प्रतिशत लगभग 75: रहा था, जो 2022 में बढ़कर 82: तक पहुँचा। इस दौरान महिला प्रत्याशियों की संख्या में भी वृद्धि हुई, परंतु उनकी वास्तविक निर्णय क्षमता पर अब भी प्रश्न बने हुए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्टों से यह भी ज्ञात होता है कि मुरैना में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, परंतु दूर-दराज़ क्षेत्रों में पहुंच अब भी एक चुनौती है।

पूर्व चुनावी आँकड़े दर्शाते हैं कि गुर्जर, ठाकुर, जाटव और यादव जैसे समुदाय प्रमुख मतदान समूह हैं। इनके बीच सत्ता परिवर्तन, जातीय गठबंधन और सामाजिक नेतृत्व के बदलते समीकरणों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। ये रिपोर्ट्स क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं को समझने में सहायक हैं।

मतदान केंद्रों की पहुंच और भौगोलिक स्थिति

ग्राम पंचायत चुनावों में मतदान केंद्रों की स्थिति का मतदाता टर्नआउट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूरस्थ या कठिन-भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्र अक्सर वृद्ध, महिलाएँ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनौती बनते हैं। एक अध्ययन में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक पहुँच कठिन होने के कारण कई मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं, और यह मुद्दा विशेषकर महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है।

स्थानीय नेतृत्व, पंचायत प्रतिनिधि और दलों का प्रभाव

ग्राम पंचायत चुनावों में स्थानीय नेतृत्व और प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली होती है। मतदाता कई बार उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, जातीय पृष्ठभूमि, तथा सामाजिक प्रभावको देखकर मतदान करते हैं, न कि दल विशेष के आधार पर। अनुसंधान दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक नेतृत्व, विशेषकर जातीय प्रमुख या प्रभावशाली व्यक्ति, चुनावी दिशा तय कर सकते हैं। कई बार प्रत्याशी की सामाजिक सक्रियता (जैसे शादी-ब्याह में भाग लेना, मदद देना) उसे वोट दिलाने में सहायक होती है, भले ही वह किसी राजनीतिक दल से न जुड़ा हो।

मतदान व्यवहार के प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा

प्रकल्पना 1: मुरैना पंचायत चुनाव में मतदान व्यवहार ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है, यह सत्य सिद्ध होता है। शोध बताते हैं कि मुरैना जैसे ग्रामीण जिलों में जातीय इतिहास, सामाजिक पदानुक्रम और राजनीतिक गुटबाज़ी मतदान को गहराई से प्रभावित करती हैं।

प्रकल्पना 2: महिलाओं, युवाओं और जातीय समूहों की निर्णायक भूमिका आंशिक रूप से सत्यसिद्ध होती है। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु निर्णय पर परिवार और जाति का प्रभाव अब भी मौजूद है; जबकि युवा मतदाता सोशल मीडिया और मुद्दों से प्रभावित होते हैं।

प्रकल्पना 3: कृषक और मजदूर दबाव समूह के रूप में कृषीमित प्रमाणमिलते हैं। सामाजिक न्याय और संसाधन वितरण जैसे मुद्दों पर किसान संगठनों की भूमिका बढ़ी है, परंतु मतदान व्यवहार मुख्यतः जाति, व्यक्ति विशेष और स्थानीय प्रभावों पर आधारित है, न कि वर्गीय गोलबंदी पर।

8.2 व्यवहारगत पैटर्न और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव

मुरैना जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक जातीय वोट बैंक अब भी प्रभावी हैं, परंतु इनके भीतर नई चेतना उभर रही है। कृषक जैसे कि महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत निर्णय लेना, युवा वर्ग द्वारा मुद्दा आधारित मतदान करना। अनुसंधान से पता चलता है कि सामाजिक रूप से हाशिए पर रहे वर्ग भी अब राजनीतिक मंच पर अधिक मुखर हो रहे हैं।

लोकतंत्र में जागरूकता और भागीदारी का निष्कर्ष

जागरूकता अभियानों (जैसे SVEEP) और मोबाइल/इंटरनेट की उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा दिया है। मुरैना के संदर्भ में देखा गया है कि महिलाएँ और युवा अब चुनावी एजेंडा पर ध्यान देते हैं, न कि केवल जातीय आग्रहों पर मतदान करते हैं (Sharma] 2019)।

विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर उत्तर

विभिन्न निर्वाचनों में एक ही मतदाता का व्यवहार कैसे बदल जाता है? मतदाता स्थानीय चुनावों में प्रत्याशी के सामाजिक संबंध, व्यवहार और ग्राम स्तर के मुद्दों (सड़क, पानी, स्कूल) को प्राथमिकता देता है। जबकि राज्य या लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय पार्टी, नेता की छवि और प्रमुख नीतियाँ (जैसे कृषि बिल, रोजगार योजनाएँ) महत्वपूर्ण होती हैं।

मुरैना जैसे क्षेत्रों में स्थानीय चुनाव राष्ट्रीय राजनीति से सीमित रूप से प्रभावित होते हैं। उदाहरणतः, यदि राज्य या केंद्र में सत्ता विरोधी लहर होती है, तो वह लोकसभा चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखती है, जबकि पंचायत चुनाव में स्थानीय नेता और सामाजिक समीकरण प्राथमिक कारक होते हैं (Ahmad et al-] 2020)।

निष्कर्ष

मुरैना जिले के ग्राम पंचायत आम निर्वाचन 2015 और 2022 का यह तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में मतदान व्यवहार अब भी सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से गहराई से जुड़ा है। जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और स्थानीय नेतृत्व मतदान निर्णय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यद्यपि महिलाओं और युवाओं की



भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन उनका मतदान अक्सर पारिवारिक या जातीय प्रभावों के अधीन होता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि मुरैना की राजनीति में जातीय गोलबंदी अभी भी प्रभावशाली है, परंतु विकास से जुड़े मुद्दे अब धीरे-धीरे मतदाताओं के विचार को प्रभावित करने लगे हैं। ग्राम स्तर पर प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, सामाजिक सक्रियता, और समुदाय के साथ संबंध चुनावी सफलता के लिए निर्णायक कारक बनते जा रहे हैं।

सूचना तकनीक, विशेषकर सोशल मीडिया और मोबाइल के प्रसार ने युवा मतदाताओं को अधिक जागरूक बनाया है। वहीं, प्रचार माध्यमों में भी बदलाव देखा गया है, जहाँ पारंपरिक माइकिंग और व्यक्तिगत संपर्क के साथ-साथ डिजिटल अभियान भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। आरक्षण नीति के चलते अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना है। लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या बनी हुई है। यदि पंचायत चुनावों को अधिक पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और प्रभावी बनाना है, तो राजनीतिक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही, जाति आधारित राजनीति की सीमाओं को चुनौती देकर विकास आधारित मतदान प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने और ग्रामीण भारत में प्रभावी शासन की दिशा में एक ठोस कदम होगा।

संदर्भ सूची

1. Ahmad, A., Bhatti, M., & Yousaf, F. (2020). Whom to Vote? Socio-psychological Factors Influencing Voting Behavior in Rural Punjab, Pakistan. , 3, 9-15.
2. Chaudhury, E. (2025). Effect of Information on Voter Turnout: Empirical Evidence from Assembly Elections in India. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
3. Deshpande, R. (2009). How Did Women Vote in Lok sabha elections 2009.



International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4. Kendre, D. (2024). Constitutional and Legal Provisions Related to Reservation Policies for Village Panchayat Elections in Maharashtra. *International Journal of Law and Society*.
5. Khatun, S. (2019). Voting Behavior of Rural Women: A Study on Laxipur Village.
6. Khatun, S. (2019). Voting Behavior of Rural Women: A Study on Laxipur Village.
7. Magstadt, T., & Schotten, P. (2010). Voting behaviour in rural and urban areas of Punjab.
8. Mori, Y., & Kurosaki, T. (2011). Does Political Reservation Affect Voting Behavior? Empirical Evidence from India.
9. Nikolenyi, C. (2010). Concurrent Elections and Voter Turnout: The Effect of the De-Linking of State Elections on Electoral Participation in India's Parliamentary Polls, 1971-2004. *Political Studies*, 58, 214 - 233.
10. Palshikar, S., & Mishra, J. (2023). Caste, Class and Vote: Consolidation of the Privileged and Dispersal of Underprivileged. *Studies in Indian Politics*, 11, 258 – 273.